

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2339 / 2012 / जोधपुर

मैसर्स को—ऑपरेटिव व्यंजनशाला,
सिवांची गेट के अन्दर, जोधपुर।

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वृत्त बी, जोधपुर।

.....अपीलार्थी

....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री नथुराम, सदस्य
श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री आर.आर.सिंघवी,

अभिभाषक।

श्री डी.पी.ओझा,

उप राजकीय अभिभाषक।

....व्यवहारी की ओर से.

....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 07.11.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे “अपीलीय अधिकारी” कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 19 / आरवेट / जेयूबी / 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 18.09.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, जोधपुर (जिसे आगे “कर निर्धारण अधिकारी” कहा जायेगा) द्वारा अवधि 2008-09 हेतु पारित आदेश दिनांक 14.02.2011 अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे “अधिनियम 2003” कहा जायेगा) की धारा 24 के तहत कायम की गई मांग में से कर राशि रु 3,69,549/-, अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति रु 7,39,098/- धारा 58 के तहत शास्ति राशि रु 290/-, अधिनियम की धारा 55 के तहत ब्याज राशि रु. 83,997/- कुल राशि रु 11,92,934 को विवादित करने पर अपील अस्वीकार की है जिससे व्यक्ति होकर व्यवसायी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलीय आदेश		कर निर्धारण आदेश			कर	ब्याज	धारा 58 के अन्तर्गत शास्ति	धारा 61 के अन्तर्गत शास्ति
		अपील संख्या	दिनांक	दिनांक	वर्ष					
1.	2339 / 11	19 / आरवेट / जेयूबी / 11-12	18.09.12	14.02.11	2008-09	3,69,549	83,997	290	7,39,098	

4. उपरोक्त अपीलों में व्यवहारी का मुख्य व्यवसाय मिठाई, नमकीन, दही, लस्सी, अचार, चपाती, पकाई हुई सब्जियां एवं पुलाव का विनिर्माण कर विक्रय करना है। व्यवहारी द्वारा चपाती को ब्रेड (Bread) के नाम पर कर मुक्त बिक्री की गई है, साथ ही पकाई हुई सब्जियों को Processed vegetables तथा पुलाव को नमकीन मानकर 4 प्रतिशत

से कर योग्य मानकर कर देय किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जांच किये जाने पर उन्होंने चपाती को ब्रेड (Bread) से भिन्न एवं पुलाव को नमकीन से भिन्न मानते हुए तथा सब्जियों को Processed vegetables से भिन्न पकी हुई सब्जी Cooked Food की श्रेणी में मानकर इन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर व्यवहारी द्वारा जानबूझकर करापवंचना मानते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश के विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपने अपीलाधीन आदेश से अपील अस्वीकार की है जिससे व्यथित होकर व्यवसायी द्वारा कर, ब्याज व शास्ति के बिन्दु पर अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

5. उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

6. व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने उपस्थित होकर कथन किया कि आलौच्य अवधि 2008–09 के दौरान कर के बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित किया गया निर्णय अविधिक है। कर निर्धारण अधिकारी ने आदेश पीछे की तिथि में जारी किया है। उन्होंने कथन किया कि व्यवहारी द्वारा चपाती (Bread) का विक्रय किया है, जो कि कर मुक्त है, इसी प्रकार Processed vegetables का विक्रय 4 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानकर किया है, इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने चपाती (Bread) को रोटी मानकर एवं Processed vegetables को पकाई हुई सब्जियों मानकर अविधिक कर निर्धारण आदेश पारित किया है। इन्होंने यह भी कथन किया कि प्रकरण में क्षेत्राधिकार स.वा.क.अ. प्रथम, वृत्त प्रथम, जोधपुर का है जबकि कर निर्धारण आदेश वा.क.अ. वृत्त जोधपुर द्वारा पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर है। इन्होंने अपील स्वीकार करने हेतु निवेदन किया। इन्होंने यह भी निवेदन किया कि अपीलीय अधिकारी ने विधिसम्मत रूप से शास्ति अपास्त की है जिससे राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. विभाग की ओर से उप राजकीय अभिभाषक ने उपस्थित होकर आलौच्य अवधि 2007–08 के संबंध में कथन किया कि व्यवहारी द्वारा करापवंचना की दृष्टि से चपाती को ब्रेड (Bread) एवं पकाई हुई सब्जियों को Processed vegetables बताकर विक्रय किया है, इस प्रकार जानबूझकर किये गये इस कृत्य के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 58 एवं 61 के तहत आरोपित की गई शास्तियां विधिक है। आगे उन्होंने कथन में व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करते हुए, विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

8. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :—

9. सर्वप्रथम क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विचार किया जाता है। अपीलार्थी का कथन है कि प्रकरण में क्षेत्राधिकार स.वा.क.अ. प्रथम, वृत्त प्रथम, जोधपुर का है जबकि कर निर्धारण आदेश वा.क.अ. वृत्त जोधपुर द्वारा पारित किया गया है जो क्षेत्राधिकार से बाहर है। इनका यह भी कथन है कि इस प्रकरण में सर्वे हुआ ही नहीं था जिससे करापवंचना का मामला बनता ही नहीं था तथा यह कहना गलत है कि धारा 61 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज हुआ था व पत्रावली इस आधार पर स्थानान्तरित की गई थी।

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 25.06.2010 से यह ज्ञात होता है कि वर्ष 2008–09 हेतु यह पत्रावली प्रारम्भ की गई है तथा व्यवसायी को नोटिस जारी किये गये हैं। व्यवसायी को बार-बार अवसर दिये जाने पर भी सूचना प्रस्तुत नहीं करने के कारण आदेशिका दिनांक 12.01.2011 में सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी ने यह कथन किया है कि व्यवहारी ने गत वर्ष की भाँति चपाती एवं Cooked Vegetable को क्रमशः कर मुक्त एवं 4 प्रतिशत कर योग्य में दिखा कर अपवंचन किया है जिससे धारा 25 सह 61 का अभियोग दर्ज हो। आदेशिका में आगे पत्रावली को आयुक्त महोदय के निर्देशों की पालना में अभियोग निस्तारण हेतु वाणिज्यिक कर अधिकारी को भिजवाने हेतु आदेश दिया है। वाणिज्यिक कर अधिकारी ने पत्रावली आदेशिका दिनांक 17.01.2011 के अनुसार पेशी में ली है। आदेशिका दिनांक 14.02.2011 में वाणिज्यिक कर अधिकारी ने कथन किया है कि व्यवहारी को समय-समय पर सम्मन जारी किये गये परन्तु उसने कोई दस्तावेज पेश नहीं किये। वाद शीघ्रकालातीत होने जा रहा है। सम्पूरित स्वविवेक से करारोपण करते हुये यह आदेश दिनांक 14.02.2011 पारित किया गया है। इस प्रकार अपीलार्थी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि करारोपण आदेश पीछे की तिथि में पारित किया है। इसी प्रकार यह कथन भी सही नहीं है कि करापवंचन का मामला नहीं होने के कारण धारा 61 का मामला ही नहीं बनता था जिससे पत्रावली स्थानान्तरण करने का आधार नहीं था क्योंकि आदेशिका दिनांक 12.01.2011 में उल्लेखित तथ्यों से स्पष्ट है कि धारा 61 का प्रकरण बनता है जिससे पत्रावली स्थानान्तरण किया जाना विधिसम्मत है। अधिसूचना प. 3(एम) / जूरिस / कर / आयुक्त / 97 / 536 दिनांक 07.08.2009 के अनुसार अधिनियम, 2003 की धारा 61 के तहत दर्ज किये गये करापवंचन अभियोग यदि सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा बनाये जाते हैं तो उनका निस्तारण वाणिज्यिक कर अधिकारी द्वारा किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार इस अधिसूचना के अनुसार कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर विधिसम्मत है। इसके अलावा विधिक स्थिति यह भी है कि वाणिज्यिक कर अधिकारी का क्षेत्राधिकार उसके सम्पूर्ण वृत्त पर होता है जिसमें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी का क्षेत्र भी सम्मिलित होता है।

10. विचाराधीन प्रकरण में द्वितीय विवादित बिन्दु यह है कि क्या व्यवहारी द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत रोटी (चपाती) व "Bread" एक ही वस्तु है अथवा भिन्न है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अनुसूची की क्रम संख्या 34 पर "Bread" कर मुक्त है तथा रोटी अवशिष्ट दर 12.5 प्रतिशत से करयोग्य है। व्यवहारी ने रोटी को कर मुक्त मानकर विक्रय किया है।

रोटी की निर्माण सामग्री आटा, पानी अल्प मात्रा में नमक है तथा "Bread" की निर्माण सामग्री मैदा, नमक, चीनी, दूध, पानी, यीस्ट आदि है जो भिन्न-भिन्न है। रोटी का निर्माण आठे की लोई बनाकर बेलकर अग्नि पर तवा रखकर या तन्दूर से सेक कर किया जाता है जबकि "Bread" का निर्माण, निर्माण सामग्री को मिलाकर पहले फरमेन्टेशन किया जाता है फिर बेकिंग (Baking) पद्धति से पका कर किया जाता है। "Bread" का प्रयोग बेकरी प्रोडक्ट के रूप में किया जाता है जबकि चपाती का प्रयोग भोजन के रूप में किया जाता है। कर देयता के विधिक इतिहास से भी "Bread" व

चपाती पर अलग—अलग कर दरें रही है। वर्ष 1988 से 1992 की अवधि में "Bread" पर 9 प्रतिशत कर दर व वेट में करमुक्त रही है जबकि रोटी हमेशा अवर्गीकृत वस्तु के रूप में रही है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सी.टी.ओ. बनाम बाबू बेकरी (1985) 58 एसटीसी 262 में निम्न प्रकार अवधारित किया गया है :—

"In common parlance when we call bread or its slices, we refer to the bread as 'bakery product'. The expression 'Cooked Food' has not been defined in the Act. It must be construed as understood in common parlance. It must be given popular sense meaning that sense which people conversant with the subject matter with which the statute is dealing would attribute to it. Reference may usefully be made to Ramavtar Budhiprasad V/s Assistant Sales Tax officer, Akola (1961) 12 STC 286 (S.C.) If a person asks for cooked food, he will not be supplied with bread of the bakery. The assessee carried on the business of bakery as the relevant time. The expression "Manufactures any goods other than 'cooked food' has some significance. There is a process of baking involved in the manufacture of bread of a bakery and it is no doubt a form of cooking but it cannot be called "Cooked Food" which is taken regularly during meal hours".

इसी प्रकार (1993) 13 आरपीजेएस 227 में भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने "Bread and Biscuit" को Cooked Food की श्रेणी में नहीं माना है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रोटी व ब्रेड दो भिन्न भिन्न वाणिज्यिक वस्तुएं हैं तथा रोटी पर नियमानुसार कर देय है।

11. विचाराधीन प्रकरण में तृतीय बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत शाही सब्जियाँ अधिनियम, 2003 की अनुसूची IV की प्रविष्टि संख्या 107 "Processed or Preserved Vegetables----" की श्रेणी में मानी जाये या नहीं।

शब्द "Vegetables" का आशय सब्जी या भाजी या तरकारी से है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल बनाम वशी अहमद (1977) 39 एसटीसी 378 में निम्न प्रकार व्यवस्था दी है :—

"It will therefore be seen that the word 'Vegetable' in the item 6 of schedule I to the Act must be construed as understood in common parlance and it must be given its popular sense meaning "that sense which people conversant with the subject matter with which the statute is dealing would attribute to it, and so construed, it denotes those classes of vegetables which are grown in a kitchen garden or in a farm and are used for the table."

सामान्य भाषा में सब्जी का आशय वही माना जायेगा जो कृषि उत्पाद है तथा जिसका प्रयोग पकाकर भोजन के साथ किया जाता है जैसे पालक, बथुआ, आलू, टमाटर आदि। ये सब्जियाँ कुछ समय बाद खराब हो जाती हैं क्योंकि इनमें जल का अंश अधिक होता है। इन्हें अधिक समय तक प्रयोग में लिये जाने योग्य बनाये रखने हेतु जो तकनीक अपनायी जाती है उसे Processing कहा जाता है परन्तु जहाँ Processing के द्वारा किसी वस्तु में पूर्ण परिवर्तन हो जाता है तो उसे निर्माण कहते हैं जो मूल स्वरूप से भिन्न होती है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मै. केशरवानी जर्दा भण्डार बनाम स्टेट ऑफ उत्तरप्रदेश व अन्य वेट रिपोर्टर वोल्यूम 11 वर्ष 2009 पेज 192 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"When by losing the identity of original product, a new product emerges and is so considered in commercial parlance too, such new product is considered to be the "manufactured goods" where as in the case of processed goods, the identity of original product neither lost nor a new product emerge."

विचाराधीन प्रकरण में व्यवहारी द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत शाही सब्जियाँ यथा छोला पनीर, गट्टा, काजू केर, मलाई, पनीर आदि हैं जो विभिन्न मसाले डालकर भूनकर तैयार की जाती हैं तो मूल स्वरूप से भिन्न नई वस्तु अस्तित्व में आती है जिसे Cooked Vegetables कहा जायेगा तथा यह Processed Vegetable वे की श्रेणी में नहीं आने के कारण इन पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर देयता मानी जायेगी।

12. विचाराधीन प्रकरण में चतुर्थ बिन्दु यह है कि व्यवहारी द्वारा निर्मित एवं बिक्रीत पकाये हुये चावल जिसे "पुलाव" कहा जाता है को अधिनियम, 2003 की अनुसूची चार की प्रविष्टि सं 131 पर अंकित अनब्राण्डेड नमकीन की श्रेणी में माना जाये या पके हुये भोजन की श्रेणी में।

सामान्य बोलचाल की भाषा में नमकीन से आशय बेसन या दाल से निर्मित भुजिया, बड़ा, कचौरी या अन्य तेल में फ्राई की हुई नमक मिर्च लगाकर तैयार की गई वस्तु है तथा पुलाव का आशय पके हुये भोजन से है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टेट ऑफ बॉम्बे बनाम विक्रम कुमार गुलाबचंद शाह एआईआर 1952 (एससी) 335 में निम्न प्रकार अवधारित किया है :—

"Even in popular sense, when one asks another have you had your food? One means the composit preparation which normally goes to constitute a meal - curry and rice, sweet meats, pudding cooked vegetables and so forth."

उपरोक्त धारणा से यह स्पष्ट है कि पुलाव Cooked Food की श्रेणी में है न की अनब्राण्डेड नमकीन की श्रेणी में।

13. इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने रोटी, सब्जी व पुलाव पर विधिसम्मत रूप से करारोपण किया है जिसे अपीलीय अधिकारी ने यथावत रखा है जो विधिसम्मत है तथा इसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. जहां तक शास्ति अपास्त करने का बिन्दु है, श्री कृष्णा इलेक्ट्रिकल बनाम स्टेट ऑफ तमीलनाडू व अन्य (2010) 26 टैक्स अपडेट पेज 1 के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर व्यवहारी द्वारा अपने समस्त संव्यवहार लेखा पुस्तकों, ट्रेडिंग अकाउण्ट में दर्शाये जाने से व्यवहारी की जानबूझकर करापवंचन करने की मानसिकता प्रकट नहीं होने से धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को विधिसम्मत एवं न्यायोचित नहीं माना जा सकता तथा इसी पक्षकार से सम्बन्धित वर्ष 2007–08 से सम्बन्धित प्रकरण में धारा 61 की शास्ति अपास्त की जा चुकी है, अतः इस आधार पर इस प्रकरण में भी शास्ति अपास्त किया जाना न्यायोचित एवं विधिसम्मत है।

15. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थी व्यवसायी की अपील आंशिक स्वीकार की जाकर धारा 61 की शास्ति अपास्त की जाती है तथा कर, ब्याज व धारा 58 की शास्ति यथावत रखी जाती है। तदनुसार अपीलीय अधिकारी व कर निर्धारण अधिकारी का अपीलाधीन आदेश कर, ब्याज व धारा 58 की शास्ति की सीमा तक यथावत रखा जाता है तथा धारा 61 की शास्ति की सीमा तक अपास्त किया जाता है।

16. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

३५४२०२
(नत्थूराम)
सदस्य